

1. मूलरूप में ही विधेयक को पारित करना ।
2. विधेयक को अस्वीकार कर देना
3. 14 दिन तक कोई कार्रवाई न करना
4. सुझावपरक संशोधनों सहित विधेयक को लोकसभा में भेजना

(3) और (4) की स्थिति में यह स्वतः समझा जायगा कि राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है। चूंकि विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक का कोई प्राधान्य नहीं है। विनियोग विधेयक तथा 'वार्षिक वित्त विधेयक' (बजट) चूंकि विधेयक है।

वित्त विधेयक - राष्ट्रपति या राज्य से सम्बद्ध कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है। यदि उसे लोकसभा अध्यक्ष ने चूंकि विधेयक के रूप में स्थापित न कर दिया हो। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं :- 1. वह विधेयक जिसमें अनु. 110 में विनिर्दिष्ट विषय निहित हैं।  
2. एक साधारण विधेयक जिसमें भारत की संघीय विधि से राज्य के संबंध में प्राधान्य निहित है।

संविधान संशोधन विधेयक - Art 368 . यह विधेयक बिली भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है मतलब कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का ही विहार बहुमत ।